VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0481289

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : ASHISH PUNIYA

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
हिन्दी

तारीख
Date
28/8/22

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)
GENERAL STUDIES (Paper III)

केंद्र
Centre MUKHERGEE NAGAR

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISION IAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISIONIAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ-साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Fiscal policy can be a key tool to reduce income inequality as well as make the poorest and the downtrodden a part of the country's growth story. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

राजकोषीय नीति का अभिप्राय सरकार कर एवं गैर कर स्रोतों से राजस्व व धन जुटाकर लोगों के कल्याण एवं पूँजीगत विकास में व्यय करती है।

बजट राजकोषीय नीति का प्रमुख टूल है।

विश्व आर्थिक असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सुपर रिच 1% के पास 22% संपदा तथा 10% लोगों के पास 57% संपदा है।

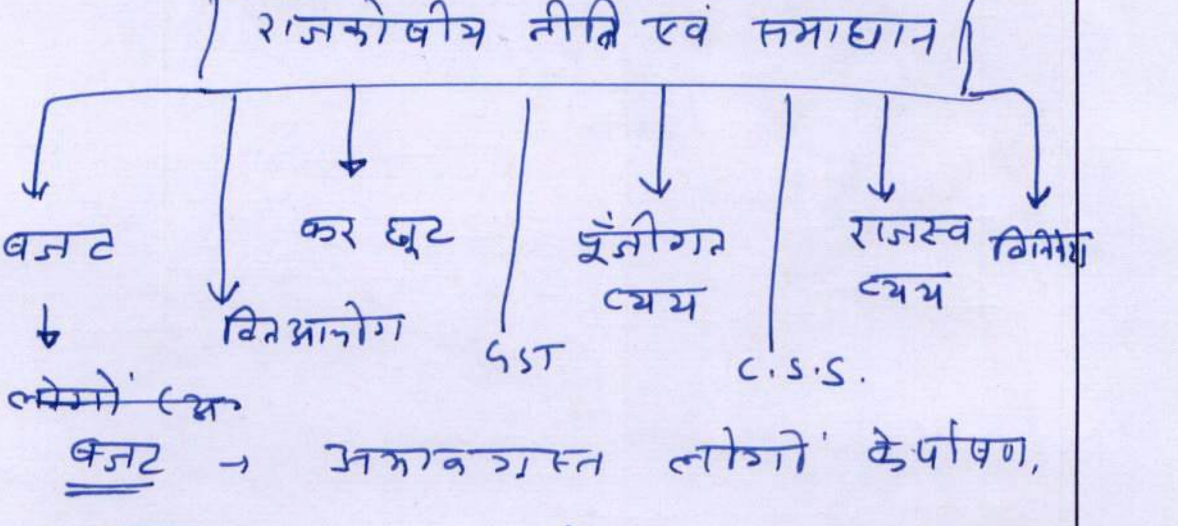

~~लोगों (स्वा~~

बजट → अभावग्रस्त लोगों के पोषण, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाकर। उदाहरण के लिए आउट ऑफ पोकेट हेल्थ खर्च →

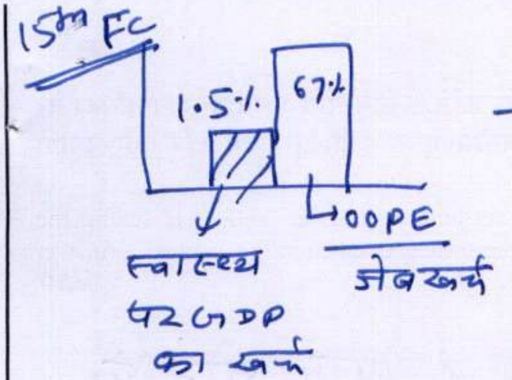

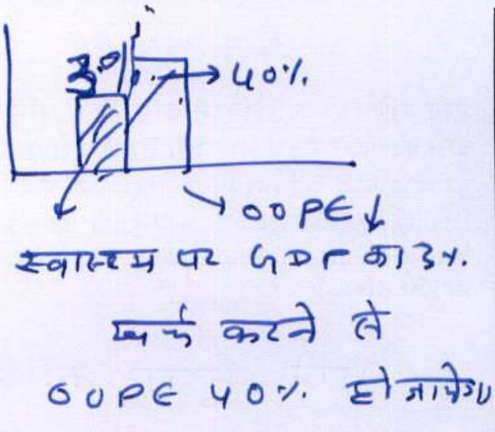

→ शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर → सामाजिक mobility हासिल करने में सहायता

पंचायतीराज संस्थाओं का विकास तथा इन्हें अनुदान देकर → पश्चिम (15th FC)

- GST की दरों को प्रगामी बनाकर → घरेलू मोरिट गुड्स का कम दरें

पूँजीगत व्यय
→ North east में अस्पताल
→ विद्यालय
→ सार्वजनिक परिवहन लागत कम

MSME का विकास।

भारत में PMGKY-अन्न → 22 माह तक निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न।

राजकोषीय नीति की गुणवत्ता व व्यापकता गरीबी निवारण एवं महामारी जनित संकट को रोकने में सहायक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना भूमि सुधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी काफी सहायक होगा। विस्तारपूर्वक समझाइए। साथ ही, इस संदर्भ में किए गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Digitizing land records will go a long way in ensuring land reforms as well as lessening the burden on the Indian Judiciary. Elaborate. Also, state the measures taken in this context. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भूमि सुधार का तात्पर्य है भूमि स्रोत के उचित स्वामित्व, उर्वरता बढ़ाने तथा भूमि के ईष्टतम उपयोग व सामाजिक सन्याय इत करने से है।

डिजिटलीकरण - प्रोजेक्ट

DI-NLRMP → 2008 - MoRD
स्वामित्व - 2020 - पंचायतीराज मंत्रालय
कर्नाटक - भूमि प्रोजेक्ट

न्यायपालिका की सहायता

① भारत में लंबित सिविल मामलों के 70% से ज्यादा भूमि से संबंधित है।
② भूमि को लेकर विवादों हेतु स्पष्ट साक्ष्यों, सीमांकन, मशीनरी का अभाव
③ डिजिटल रिकॉर्ड → विवादों को कम
↳ साक्ष्य प्रणाली मजबूत
↳ न्याय प्रदायगी में स्फूर्ति

उदा० के लिए वसीम जिला, महाराष्ट्र

जिला प्रशासन ने लैंड बैंक
- नजूल भूमि
- राजकीय भूमि
- कृषि भूमि

→ विवाद कम
→ औद्योगीक विकास हेतु लीजिंग
→ उपयोग पैटर्न की गुणवत्ता

आगे की राह व उपाय

→ नेशनल मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को नहीं अपनाया गया, पर राज्यों को छोड़
→ FRA कानून → odisa, mp मॉडल
→ PESA, पंचायतों का भूमि पर नियंत्रण
→ NLMC (लैंड प्रबंधन निगम - वाणिज्य मंत्रा.)

भूमि डिजिटलीकरण द्वारा स्वामित्व एवं भूस्वामियों की बैंक तक पहुँच बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था में गुणात्मक प्रभाव निर्मित होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन-मेरिट सब्सिडी के लिए निधि (फंड) उपलब्ध कराने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति, भारत में कुछ राज्यों को गंभीर राजकोषीय संकट के कगार पर धकेल रही है। इस संदर्भ में, भारत में सब्सिडी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
It has been pointed out that competitive politics to fund mostly non-merit subsidies is pushing a few states in India to the brink of a deep fiscal crisis. In this context, discuss the need to rationalise the subsidy regime in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सर्वोच्च न्यायालय ने नॉन मेरिट सब्सिडी तथा मुफ्त उपहार प्रथा को रोकने लिए वित्तआयोग जैसी निष्पक्ष व स्वायत्त संस्था द्वारा समुचित नीति निर्माण के लिए आह्वान किया है।

राजकोषीय संकट

→ 2021-22 → भारत का ऋण-GDP अनुपात 85%
तथा राज्यों का 35%
(जबकि FRBM के तहत सीमाएँ 60% व 20% है।

② उदा० तेलंगाना द्वारा कुल राजस्व व्यय का 40% लोककल्याणकारी योजनाओं पर

③ राजस्व व्यय ↑ पूँजीगत व्यय ↓

→ राजस्थान सरकार के राजस्व व्यय का 56% केवल वेतन व पेंशन पर (old pension)

तथा पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली घोषणाएँ

आगे की राह

→ सब्सिडी एवं फ्रीबी में सीमारेखा निर्धारण

→ वित्त आयोग को स्थायी निकाय व निगरानी तंत्र

→ mcc (आचार संहिता) को विधिक → mcc के chapter 8 में बनाना

→ राजकोषीय प्रबंधन

15th वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने कहा कि नॉन मेरिट सब्सिडी को बिना विधानमंडल व संसद के अनुमोदन देना राजकोषीय अविवेक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. सूक्ष्म-सिंचाई में कृषि को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में परिवर्तित करने की वृहद् क्षमता है। दिए गए कथन की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Micro-irrigation has tremendous potential in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Discuss the given statement in the context of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सूक्ष्म सिंचाई का अभिप्राय: दक्ष सिंचाई एवं बूंद बूंद प्रणाली से है जो परंपरागत बाढ़ सिंचाई के मुकाबले कम जल दोहन करती है।

PMKSY कृषि सिंचाई योजना।

- AIBP
- जल संभर विकास
- Per drop, more crop
- फर्टिगेशन & मल्चिंग

- PMKSY हर खेत तक पानी पहुँचाने के उद्देश्य से → कृषि विकास में गुणवत्ता
- यह योजना जल के "कैच द रेन" तथा धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक
- सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों द्वारा फर्टिगेशन व मल्चिंग भूमि की उर्वरता व गुणवत्ता को नकारात्मक प्रभावित नहीं करते

- भूजल दोहन पर रोक
- crop diversification एवं मोटे अनाज की कृषि पर ध्यान केंद्रित करना
- छोटे आकार के खेतों की उत्पादकता में वृद्धि।

आगे की राह

- PM-KUSUM का कुशल क्रियान्वयन एवं PMKSY के साथ अभिसरण
- मिहिर शाह आयोग की सिफारिशें
- waterplus प्रोटोकॉल
- इजराइल से I2U2 संगठन के तहत ड्रिप सिंचाई तकनीक साझा करने पर ध्यान केंद्रित।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. भारत के विशाल संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपीय देशों (PSIDS) की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Given its vast resources and technical expertise, India can play a key role in assisting the Pacific Small Island Developing States (PSIDS) in dealing with the impact of climate change. Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PSIDS छोटे एवं द्वीपीय राष्ट्र है जिनका जलवायु परिवर्तन में योगदान नगण्य है तथा इनके जलमग्न होने का खतरा हमेशा रहता है। भारत हमेशा से इनके लिए जलवायु न्याय की मांग करता आया है।

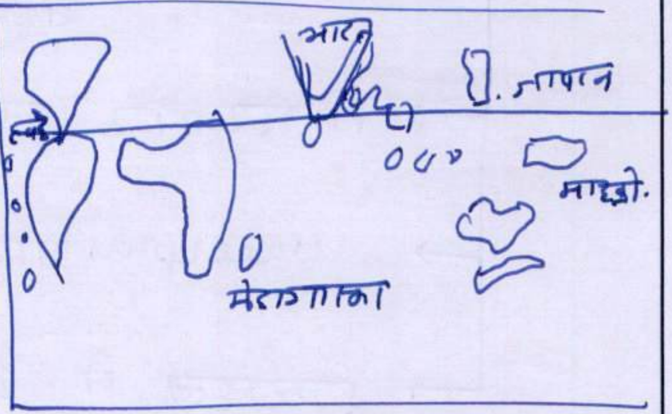

प्रमुख बिन्दु

① भारत CDRI (आपदा प्रत्यास्थता पहल) के माध्यम से ज्ञान साझा

② 2004 सुनामी के बाद QUAD का गठन एवं ITEWS (सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम)

③ QUAD+ तक विस्तार

④ छोटे लघु द्वीपीय देशों को चाइना की चेक बुक पॉलिसी

का खतरा, ऐसे में भारत एक भरोसेमंद साथी के रूप में

→ माइक्रोनेशिया, फिलीपीन्स, जापान आदि तक सहयोग रणनीति में विस्तार

→ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व मदद

- आपदा
  - सुनामी
  - चक्रवात
- वर्षा पैटर्न
  - R&D
  - ICAR
- एक्वाकल्चर
  - WTO में IUU मामलों में द्वीपीय देशों का पक्ष
- जलवायु न्याय
  - CBDR

INCOIS तथा ISRO जैसी संस्थाएं समुद्र एवं अंतरिक्ष दोनों स्तरों पर सहायता हेतु प्रतिबद्ध है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. हालिया "पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR)" का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा प्रत्यास्थता विकसित करना है। इस संदर्भ में, इस योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी तर्क की विवेचना कीजिए और इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
The recent "Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj (DMP–MoPR)" aims to develop disaster resilience at the grassroots level. In this context, discuss the rationale behind the formulation of the Plan and highlight its key components. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कोविड-19 में आपदा प्रबंधन को लेकर पंचायतीराज संस्थाओं की व्यापक भूमिका को सामाजिक पूँजी निर्माण के क्षेत्र में रेखांकित किया गया।

DMP-MOPR, आपदा प्रबंधन योजना 2016 का व्यापक विस्तार है जो क्षमता विकास, समन्वय एवं प्रत्यास्थता में विस्तार करेगा।

प्रमुख घटक

① DMP-MOPR → पंचायतीराज संस्थाओं को व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया SOP प्रदान करती है।

② पेयजल, आजीविका एवं लाइवस्टोक से संबंधित घटक

③ आपदा प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के घटक का समावेश

④ ग्राम स्वयंसेवी तैयार करना

प्रमुख तर्क व उपागम

- → स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका।
- → जमीनी स्तर पर आयोजना विकास
- → आपदा को रोजगार तथा स्वावलंबन के अवसर में बदलना
- → रणनीतिक उपागम एवं जीरो फैटेलिटी अप्रोच

Model स्थानीय ज्ञान

2004 सुनामी

top down → चेन्नई में भयंकर तबाही

bottom up → टेंटीनलीज लोगों के पारंपरिक ज्ञान → बहुत कम fatality (10 से कम)

इस प्रकार उपरोक्त उपागमों से जमीनी स्तर पर उत्पादक्षम विकास किया जा सकेगा।

7. राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (EDT) के उपयोग से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा संबंधी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the internal security implications emanating from the use of Emerging And Disruptive Technologies (EDT) by state and non-state actors. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगीकी आंतरिक सुरक्षा में भारी खतरा उत्पन्न कर सकती है, यह शत्रु को समझने में देर करती है (सुरक्षा एजेंसियों को)।

EDT
→ साइबर हमले
→ सोशल मीडिया
→ ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी
→ बॉम्ब एवं लोन वुल्फ अटैक
→ ड्रोन tech.

राज्यों द्वारा

① पाक द्वारा IB के निकट ड्रोन निगरानी की रचना

② चीन द्वारा (Huwave) → संप्रभुता को खतरा।

③ चीन 30000 PLA सैनिकों व 1.5 लाख लोगों को साइबर वारफेयर के लिए तैयार किया।

④ पनडुब्बी → श्रीलंका में चीन की रिसर्च जहाज

गैर राज्यों द्वारा

→ LET, ISIS द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती

→ भड़काऊ पोस्ट → हेट स्पीच

→ रैनसमवेयर,

→ क्रिप्टोजैकिंग → ब्लॉकचेन पर नियंत्रण

~~WEF की~~ इन्हीं कारणों से भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 12 वां सुभेद्य राष्ट्र है।

आगे की राह
→ साइबर रक्षा योद्धा
  → महत्वाकांक्षी
→ NCCPCR (क्रिटीकल इंफ्रा)
→ सीमा सुरक्षा
→ ड्रोन नियमन

WEF ने टिप्पणी की है कि जिस गति से तकनीकें विकसित हो रही हैं उस तीव्रता से सरकारों के सुरक्षा कानून ~~नहीं~~ प्रगति नहीं कर पा रहे हैं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में भारत द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Identify the impediments faced by India in boosting its defence exports. Also, discuss the steps taken by the government in this regard. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत ने 2021-22 के दौरान 13000 करोड़ रु का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है, जो इसकी 75 देशों तक निर्यात विस्तार को दिखाता है।

उठाए गए कदम

① रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
- रक्षा उद्योगों के घरेलू विनिर्माण पर बल तथा नकारात्मक आयात की 200 वस्तुओं की सूची

② ऑफसेट नियमों का युक्तिसंगतकरण

③ रक्षा विविधीकरण
- तेजस - सफलता
- ब्रह्मोस - फिलीपीन्स
- US → ग्लोबल मार्केट के निर्माण में प्रमुख हाँथ।

④ रक्षा ज्ञान नेटवर्क → RPR हेतु

⑤ IDEX → नवोन्मेष प्रदर्शन

⑥ सार्वजनिक क्षेत्र का विकास → HAL, BEL

बाधाएँ

① तकनीकी बाध्यताएँ → ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पार्क में रूसी → ~~रूस~~ की निर्भरता द्वारा अधिकतम निर्भरता।

② धन व प्रशिक्षित कार्यबल

③ तकनीकी हस्तांतरण का अभाव

④ निजी क्षेत्र की भागीदारी 90% से घटकर 70% हुई

⑤ उदासीन नीतियाँ → आर्मेनिया द्वारा नागोर्नो - काराबाख युद्ध में

भारत का निर्यात SIPRI के अनुसार 29 वें स्थान पर है जो बाजार में 2% से कम है अतः व्यापक सुधार की संभावना व गुंजाइश विद्यमान है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. अंतरिक्ष मलबे से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस खतरे से निपटने के लिए हाल के दिनों में की गई पहलों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the multiple issues associated with space debris. Also, state the initiatives taken in recent times to tackle this menace. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अंतरिक्ष मलबे में शामिल हैं -
- → अंतरिक्ष अप्रयुक्त उपग्रह
- → प्रमोचन यानों द्वारा छोड़े गए पुर्जे
- → रॉकेट का पिछला हिस्सा

वर्तमान में LEO में 400km तक लगभग 26000 पीस उपस्थित है जिसमें से कुछ अंतरिक्ष मलबे में योगदान दे रहे है।

मुद्दे
- केसलर सिंड्रोम → व्यापक टक्करों की श्रृंखला
- विद्युत, इंटरनेट ग्रिड को खतरा
- अंतरिक्ष कार्यक्रमों की लागत ↑ → उपग्रहों की रक्षा व निगरानी
- ASAT → एंटी satellite गतिविधियाँ

• अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को खतरा

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल की पहलें

→ ESA (यूरोपीय) द्वारा मिशन
DEBRIS → नेट कल्चर / हार्पून कल्चर → तकनीकें

→ India-USA → स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट

- भारत → ISRO + DRDO प्रोजेक्ट नेत्र

- इसके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आउटर स्पेस संधि

अंतरिक्ष मलबा वैश्विक
दूरसंचार, बुनियादी सेवाओं के लिए
खतरा है। अतः UN COPUOS के
तहत व्यापक रणनीति बनानी होगी।

10. भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को अपनाने से उपभोक्ताओं के लिए ई-कॉमर्स के अधिक समावेशी और सुलभ बनने की संभावना है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The adoption of Open Network for Digital Commerce (ONDC) in India is expected to make e-commerce more inclusive and accessible for consumers. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संसद की उपभोक्ता मामलों पर स्थायी समिति के अनुसार भारत में E-com बाजार का 95% हिस्सा वॉलमार्ट व अमेजन केवल दो फर्मों के पास है, जो मोनोपॉली की स्थिति है।

* DPIIT (वाणिज्य मंत्रालय) ने इस संदर्भ में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रस्तावित

- ओपन सोर्स नेटवर्क
- सभी फर्मों को समान अवसर
- रुपे व UPI की तर्ज पर सार्वभौमिकता
- सभी उत्पाद / सभी फर्म / सभी मूल्य
- उचित पारदर्शिता एवं बाजार प्रतिस्पर्धा का विकास

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

आगे की राह

- इन्वेंटरी मॉडल के बजाय → उपभोक्ता केंद्रित उपागम
- स्टार्टअप को डिलीवरी सेवा बाजार में प्रवेश
- E-com कंपनियों द्वारा कॉल बैक लायबिलिटी का पालन करना।
- CCPA, CCI, dpiit में समन्वय
- Rurban क्षेत्रों में नमो ड्रोन से डिलीवरी हेतु प्रावधान

इस दिशा में केरल सरकार का "केरल सवारी" स्कॉलर्स प्रणाली ~~तथा~~ उल्लेखनीय है जो इस नए सेक्टर में सरकारी भागीदारी तथा एकाधिकारवादी प्रथाओं को रोकने में सहायक है।

11. यद्यपि, हाल ही में "क्षतिकारक" सरकारी मत्स्यन सब्सिडी को रोकने के लिए डब्ल्यू. टी. ओ. के मंच पर एक समझौते पर सहमति बनी है, तथापि, भारत द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं से पता चलता है कि इस मामले में और अधिक वार्ता किए जाने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
While an agreement was recently reached at the WTO on a deal to curb "harmful" government fisheries subsidies, certain concerns raised by India suggests that the matter will require further negotiations. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में IUU (इररेगुलेटेड, अनारिपोर्टेड, अनसस्टेनेबल) मत्स्यन पर रोक लगाने की चर्चा हुई।

IUU
- → FAO द्वारा प्रस्तावित शब्द
- → बॉटम ट्रॉलिंग, डायनामाइट फिशिंग
- → विदेशी व्यापार को बाधित

हालांकि भारत को मछुआरों के हित में 2024-25 तक सब्सिडी दिए जाने के संदर्भ में छूट मिल गई है।

भारत द्वारा उठाई गई चिंताएँ

- → भारत में 2 करोड़ मछुआरों के जीवन पर प्रभाव (अप्रत्यक्ष रूप से 4 crore लोगों पर
- → ~~भारत~~ मछुआरा समुदाय की आजीविका में विविधता के अवसरों की कमी

- मत्स्यन को लेकर द्वीपीय देशों एवं हिन्दमहासागर क्षेत्र के देशों की बाध्यताएं

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

— विकासशील देशों में तकनीकी विकास नहीं
- एक्वाकल्चर
- ओरनामेंटल मत्स्यन
- प्रोसेसिंग उद्योग

- भारत ने SIDD (लघु द्वीपों) तथा विकासशील देशों को IUU प्रावधानों से छूट की मांग रखी

और वार्ता एवं आगे की राह

1. तकनीक हस्तांतरण का प्रावधान → विकासशील व द्वीपीय देशों को
2. लघु व कम आय वाले देशों के साथ S&DR स्पेशल एंड डिफरेंट व्यवहार की मांग
3. घरेलू मछुआरों के गरीबी को ध्यान में रखते हुए PM किसान/संपदा के (कल्याण) तहत अवसंरचना निर्माण
4. प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

- पोषण एवं खाद्य जरूरतों का ध्यान रखना

इस दिशा में मीना कुमारी कमेटी की सतत ब्लू इकॉनमी तथा FAO का सस्टेनेबल मत्स्यन विकास मॉडल अनुकरणीय है।

/

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. सड़क निर्माण क्षेत्रक में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) से जुड़े लाभों के बावजूद, विभिन्न कारणों से इसमें रुचि कम हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite the advantages that are associated with the hybrid annuity model (HAM) in the road construction sector, the interest in it has moderated due to various reasons. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

HAM हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल में सार्वजनिक व निजी भागीदारी के दो मॉडल BOT तथा एन्यूटी मॉडल का समावेश होता है।

उदाहरण के लिए ⇒ भारतमाला प्रोजेक्ट में HAM मॉडल को अपनाया गया।

HAM के लाभ

1. सरकार की जिम्मेदारी → रणनीतिक सहायता, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, 40% वित्त
2. निजी क्षेत्र की भूमिका 60% वित्त जुटाना तथा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना
3. जोखिम एवं लाभों का परस्पर व साझा बंटवारा।

लेकिन CAG की रिपोर्ट के मुताबिक भारतमाला के HAM प्रोजेक्ट 6 वर्ष की देरी से पूर्ण

होने की संभावना है।

कम रुचि के कारण

① निजी क्षेत्रों पर अत्याधिक दबाव
वित जुटाने को लेकर बाध्यताएँ
→ क्राउडिंग आउट इफेक्ट
– IL & FS संकट (NBFC)

② अधिकतर प्रोजेक्ट कम रिटर्न से
युक्त → नॉर्थ ईस्ट में सड़क विकास
↳ हाइ इंपैक्ट कम्युनिटी डवलपमेंट
प्रोजेक्ट (HICDPs)

③ लालफीताशाही व पर्यावरण मंजूरी
भी प्रोजेक्ट को समय पर पूर्ण
करने में बाधक

④ सरकारी वित्त उपलब्धता में देरी
↳ वित्तसंग्रहण स्वाभाव

आगे की राह

→ कोरपोरेट बॉन्ड विकास
→ वित्त संग्रहण में PPP
एजेन्सी प्रकोष्ठ में

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

• सुधार एवं आधुनिकीकरण

• राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट को लेकर व्यापक सहमति → ब्लूप्रिंट स्टेज में ही

eg- तूतीकोरिन स्टरलाइट कॉपर प्रोजेक्ट आदि

इस दिशा में बजट 2022-23 का 1000 Cr के कैपीटल से शुरू मवसंरचना विकास बैंक (NaBFID) का निर्माण उल्लेखनीय है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

13. मौजूदा एम. एस. पी. खरीद व्यवस्था न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही कृषि-पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय है। सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही, मौजूदा एम. एस. पी. व्यवस्था में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The existing MSP procurement regime is neither economically nor agro-ecologically sustainable. Elaborate. Also, evaluate the alternative approaches that can be adopted to improve the existing MSP regime. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कृषि सुधारों पर एकमत निर्माण एवं नवोन्मेषी सुझावों हेतु गठित संजय अग्रवाल पैनल ने पाया कि भारत में

MSP से → केवल कुछ राज्यों को लाभ
PB & HR, UP
→ 2% से कम किसानों तक पहुँच
→ केवल 0.9% तिलहन व 7% दलहन की खरीद
↓
केवल गेहूं व चावल पर केंद्रित

तथा यह कृषि पारितंत्र के लिए भी असंधारणीय है -

(i) तेट आभासी जल व्यापार → 1kg चावल उगाने में 2000 liter जल

(2) भूजल दोहन → 85% भूजल का प्रयोग कृषि में

3. फसल विविधीकरण का अभाव, मोटे अनाजों को प्रोत्साहन नहीं

4. पराली जलाने से → उर्वरता, उर्वरता एवं वायु गुणवत्ता प्रभावित

सुधार के लिए विकल्प

→ ① मोटे अनाजों पर msp तो है (जैसे बाजरा 2200 ₹/क्विंटल), लेकिन FCI की पहुँच → Raj, गुजरात तक नहीं
⇓
शांताकुमार कमेटी → FCI में संस्थागत बदलाव

② गेहूं व चावल को NFSA में कुछ हद तक बाजरा, मक्का से प्रतिस्थापन → MDM, पोषण योजना आदि में

③ MSP योजना को युक्तियुक्त बनाना
→ पूर्वानुमेयता
→ उच्च सिंचाई फसलों के हतप्र बढ़ाना

④ PM- आशा का क्रियान्वयन

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

BSP व्यवस्था को नियमित व व्यवस्थित बनाकर, भंडारण व्यवस्था को आधुनिक विकास करके, सीमान्त व लघु किसानों की उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करना, MS स्वामीनाथन के स्वप्न सदाबहार क्रांति को पूर्ण करेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. यह तर्क दिया जा रहा है कि भारत गोदामों में खाद्यान्नों की अधिकता से जूझ रहा है। भारत की मौजूदा बफर स्टॉक नीति को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
It is being argued that India is struggling with overflowing foodgrains in warehouses. Discuss the statement in view of the existing buffer stock policy of India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

खाद्य विभाग एवं उपभोक्ता मामलों के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अगले 5 वर्षों तक की आवश्यकता हेतु खाद्यान्न गोदामों में उपलब्ध है।

मौजूदा बफर स्टॉक नीति

- FCI द्वारा गेहूं व चावल की अत्यधिक खरीद, NFSA के तहत वितरण
- बफर स्टॉक नीति में उचित समय सीमा का लक्ष्य नहीं, गोदामों में अनाज के सड़ने का संकट
- FAO के डाटा के अनुसार पोस्ट हार्वेस्टिंग एवं भंडारण के दौरान भारत में लगभग 16% अनाज बरबाद
- आवश्यकता वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 निजी भंडारण व्यवस्थाओं को निषेध करता है, हतोत्साहन प्रदान करता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आगे की राह

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास
- रूस - यूक्रेन युद्ध जनित खाद्य संकट एवं विकासशील देशों को निर्यात
- PMGKY - ~~मन्न~~ अन्न वितरण
- बफर स्टॉक नीति का विकास एवं आवधिक समीक्षा।

शांताकुमार कमेटी के अनुसार FCI में संस्थागत बदलाव करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. हाल ही में, सरकार ने सभी पत्तनों (पोर्ट्स) को वर्ष 2047 तक स्वयं को 'मेगा पोर्ट्स' के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देश दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में, पत्तनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और साथ ही, भारत की ब्लू इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the government has asked all ports to prepare a master plan in order to become 'mega ports' by 2047. In light of this, discuss the challenges faced by ports and suggest remedial measures in order to propel India's blue economy. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में दिल्ली से माल की खेप को मुंबई के बंदरगाह से अमेरिका पहुँचने में 41 दिन का समय लगता है जो अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है।

तथा WB की लॉजिस्टिक परफोर्मेंस इंडेक्स में भारत का 44 वाँ स्थान है।

भारत में पत्तन

1. मेजर पोर्ट → केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
2. माइनर पोर्ट → राज्य सरकारों द्वारा संचालित

चुनौतियाँ

① समय ज्यादा लगना,
② माल ढुलाई के लिए तकनीकें उपयुक्त नहीं

3. पोर्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी विकास नहीं
- → AI
- → ब्लॉकचेन तकनीक
- → सिस्टम क्लियरेंस में देरी

4. स्थानीय पत्तनों में गाद की समस्या

5. भारी भार वाले जहाज श्रीलंका कोलंबो पोर्ट पर ठहरते हैं।

6. अवसंरचना विकास नहीं
- → ड्राई पोर्ट
- → बंदरगाह प्रबंधन

उपाय

नीतिगत व कानूनी

1. मेजर पोर्ट एक्ट 2020 → प्रबंधन में स्वायत्तता
2. मॉडल पोर्ट विधेयक

संस्थागत → शीप बिल्डिंग विकास
- → पोर्ट मॉडल
  - → लेंड लॉर्ड मॉडल
  - → सर्विस पोर्ट विकास

3. तकनीक → block chain
4. क्लियरेंस → Icegate

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. क्रेडिट गारंटी - विस्तार

6. <u>नारीशक्ति</u> → आत्मनिर्भरता - सशक्त

Silos दूर करना

7. लॉजीस्टिक समझौते → LEMOA आदि

इस दिशा में सभी प्रयत्नों का समग्र विकास भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा तथा मीना कुमारी कमेटी की रिपोर्ट समग्रत: ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. आय और संपदा में असमानता कार्बन असमानता में परिवर्तित हो जाती है। इस संदर्भ में, भारत के लिए कार्बन असमानता को दूर करने के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसे प्राप्त करने के उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Inequality in income and wealth translates into carbon inequality. In this context, discuss the significance of addressing carbon inequality for India and suggest ways to achieve it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कार्बन असमानता का तात्पर्य है उच्च राष्ट्रीय उत्सर्जन के बावजूद प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन एवं उपयोग के मामले में पिछड़ापन।

यथा - केंद्रित भारत

(a) कार्बन का विश्व का तीसरा बड़ा उत्सर्जक → USA > China > india

(b) लेकिन प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन 1.8 टन/yr जबकि वैश्विक औसत 4 टन/yr

आय व संपदा असमानता
→ india विश्व असमानता रिपोर्ट

सुपर रिच 1% लोग	22% संपदा व आय
top 10%	57% संपदा

आय व संपदा असमानता	कार्बन असमानता
1. उच्च वर्ग द्वारा उत्सर्जन ज्यादा	→ गरीब व कमजोर वर्ग को संकट बाढ़, जलवायु परिवर्तन, कृषि नुकसान
2. ऊर्जा उपयोग में भिन्नता	प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग 1183 kW वैश्विक औसत का एक तिहाई
3. पोल्यूटर सैल पे के बजाय	इन्सोलेंट शोल्डर पे की स्थिति
4. कूलिंग आवश्यकता ज्यादा	जल स्रोत/कोल्ड प्रथाएँ बाधित

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कार्बन असमानता पिछड़े व कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य, जीवन के अवसरों को सीमित करता है।

अतः SDG-12 के अनुसार सतत व संधारणीय उत्पादन व उपभोग पैटर्न व रणनीति की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. भारत में पिछले एक दशक के दौरान भूस्खलन की बढ़ती और नियमित घटनाओं के बावजूद, विकास के प्रमुख प्रतिमानों (पैरडाइम) में कोई मुख्य संशोधन नहीं किया गया है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite increased and regular occurrences of landslides over the past decade in India, the dominant development paradigm has largely not been modified. Examine. (Answer in 250 words)15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भुस्खलन का आशय है पहाड़ी, चट्टानी मलबे का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में खिसकने से है जो बाढ़, बादल फटने की घटनाओं से जोखिम की तीव्रता को और ज्यादा दुर्भेद्य बना देता है।

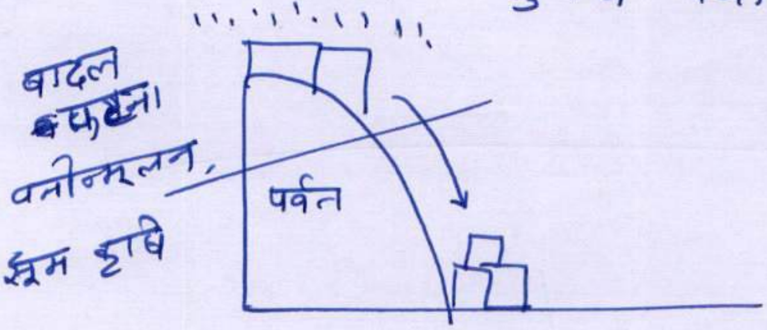

पिछले एक दशक

BRO तथा GSI के लैंडस्लाइड हेजार्ड जोनेशन के अनुसार। पिछले एक दशक में भूस्खलन की आवृत्ति 40% से ज्यादा बढ़ गई है।

उदा. - 2013 → केदारनाथ
→ 2017 → बारामूला
→ 2020 → कश्मीर
→ 2021 → अन्नाइमुडी

चुनौतियाँ

- → रणनीति ज्यादातर मामलों में रिकवरी एवं रिहेबिलेटेशन पर आधारित, आपदा पूर्व रणनीति पर ध्यान कम

- → NDMA द्वारा दिशानिर्देशों के बावजूद अंतर एजेंसी समन्वय का अभाव
- → बसावट पैटर्न में बदलाव नहीं, बढ़ती आबादी पर नियंत्रण → पहाड़ी क्षेत्रों में

भारतीय आबादी

1950	2020
50 milion	260 milion

- → प्रतिमानों में समय के साथ बदलाव नहीं
  - → GLOF, बादल फटना } complex disaster

आगे की राह

- → क्षमता विकास तथा Proffessionals का काडर विकास
- → भूस्खलनरोधी task force
- → आयोजना → संधारणीय पर्यटन

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास पर नियंत्रण।

- समग्र नीति
  - GLOF
  - बादल फटना
  - बाढ़
  - हिमस्खलन

- स्थूल वृद्धि रोकना।

इस प्रकार इस क्षेत्र में पड़ोसी देशों से CDRI के तहत ज्ञान साझा करने एवं तिब्बत सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ वैध सीमा-पार प्रवाह को संतुलित करने के लिए भारत को एक स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India needs a smart border management system to balance legitimate cross border flows with national security interests. Discuss. Also, highlight the initiatives taken by the government in this regard. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्मार्ट बोर्डर मैनेजमेंट से आशय है कि राष्ट्रीय सीमाओं का प्रभावी रेखांकन, उनकी सुरक्षा और बिना अनुमति के आवागमन पर पूर्णत: नियंत्रण होना है।

वैध सीमा पार प्रवाह

- → विदेशी व्यापार
- → नदी तंत्रों एवं जलसंभर विकास, लेकिन अवैध आप्रवासन हो
- → इंटीग्रेटेड चेक पोइन्ट
- → प्रत्येक आने जाने वाले का रिकॉर्ड प्रबंधन

क्यूँ आवश्यक

- सीमापार से राज्य व गैर राज्य कर्ताओं का खतरा → पाक, चीन तथा ULFA, NSCN, HUJI
- बांग्लादेश के साथ छिद्रिल सीमा - अवैध प्रवास → NRC बाधाएँ
- म्यांमार से रोहिंग्या

-

- चीन की विस्तारवादी नीति
- नेपाल द्वारा नक्शा बदलना → लिम्पियाधुरा व लिपुलेख पर दावा

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सरकार के प्रयास

- सीमा सुरक्षा बल, ITBP, असम राइफल्स बलों का आधुनिकीकरण
- 15th FC रक्षा बलों का आधुनिकीकरण का नॉन लाप्सेबल फंड → 34000 cr
-

① पाक बॉर्डर पर CIBMS तंत्र की स्थापना (मधुकर गुप्ता कमेटी)

② कश्मीर LOC पर NSG की तैनाती

③ बांग्लादेश सीमा पर निगरानी
↓
BOLD QIT

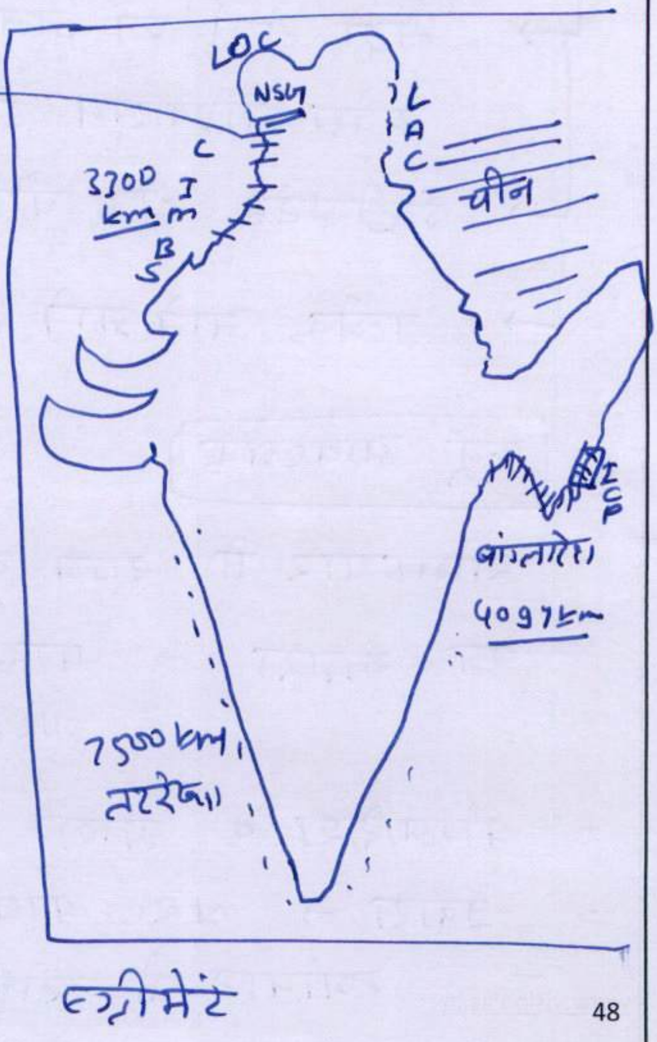

- लैंड बाउंडरी एग्रीमेंट

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

④ म्यांमार सीमा पर 13 ICP इंटीग्रेटेड चेक पाइंट का विकास

⑤ चीन सीमा पर गलवान घाटी पर सेना के पहुँचने के अवसंरचना विकास

↓

100 km क्षेत्र में निर्माण हेतु पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं

इसप्रकार 15000 km लंबी सीमा के बहुआयामी संकटों का समाधान बाड़ेबंदिंग, स्मार्ट तकनीकों के साथ अन्य उपायों से किया जा रहा है।

19. वैश्वीकरण और धन शोधन के बीच संबंध स्थापित करते हुए, इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Establishing linkages between globalisation and money laundering, discuss the initiatives taken at the national and international levels to combat it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PMLA कानून 2002 (संशोधन) 2015 के धारा 3 के तहत धनशोधन का अभिप्राय अवैध धन जुटाने, एकीकरण तथा लेयरिंग से लेकर उसे अर्थतंत्र में प्रवेश कराने वाली प्रत्येक गतिविधि शामिल होती है।

जबकि FATF के तथ्यों के अनुसार मुक्त व्यापार एवं वैश्वीकरण ने भी धन शोधन को प्रभावित किया है

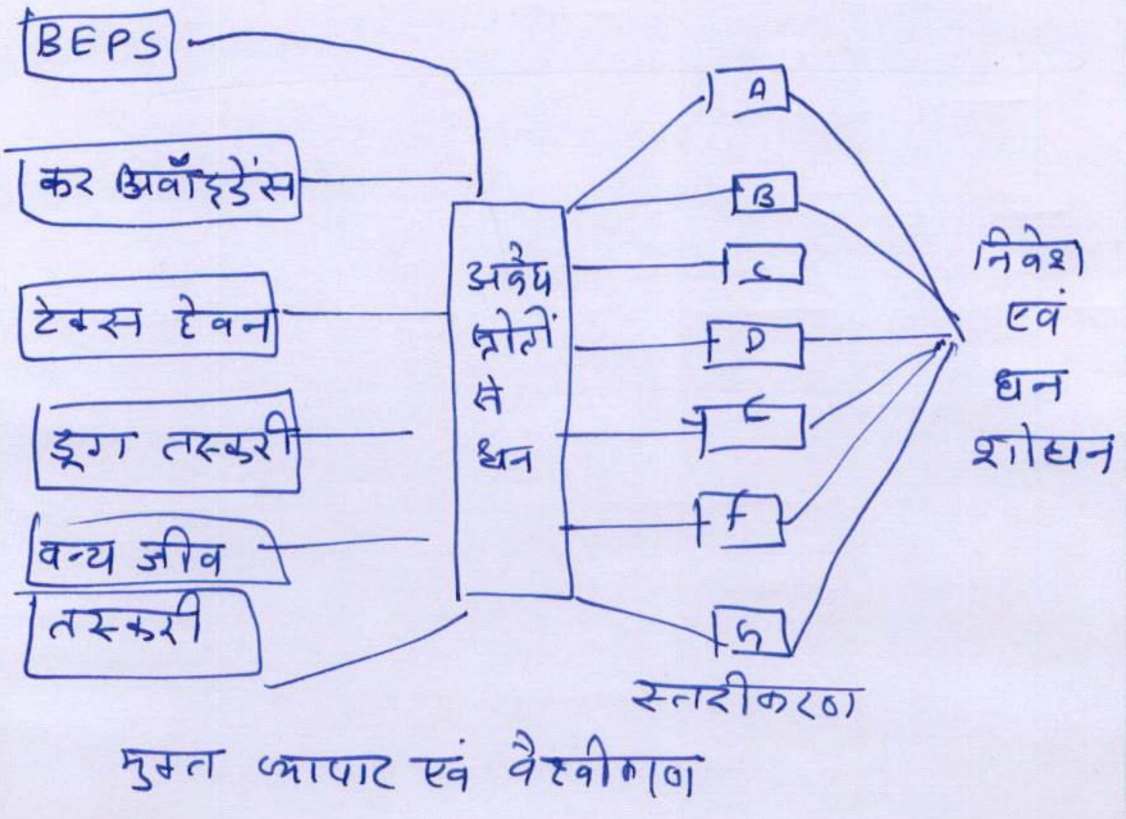

मुक्त व्यापार एवं वैश्वीकरण

अंतर्राष्ट्रीय पहलें

1. G-7 द्वारा FATF का गठन
   - ↳ AML / CFT कानूनों के निर्माण में सहायता
   - ↳ AML / CFT गतिविधियों पर निगरानी
2. CITES → अवैध वन्य जीव व्यापार व धनशोधन रोकना
3. UNODC → नार्को ट्रेड एवं धनशोधन पर रोक
4. क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन - सोशल मीडिया के माध्यम से धनशोधन व आतंकवाद को रोकना।

राष्ट्रीय स्तर पर

1. नीतिगत व विधायी
   - धनशोधन निवारण कानून 2002 (2019 संशोधन)
   - UAPA एवं NIA एक्ट
   - NDPS एक्ट → ड्रग्स व्यापार से धनार्जन
2. संस्थागत स्तर पर
   - ED (प्रवर्तन निदेशालय)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- RBI (फोरेन एक्सचेंज पर निगरानी)
- FATF के नियम अपनाना (BEPS आदि)
- FIU - वित्तीय आसूचना तंत्र

हालिया कदम

→ नोटबंदी 2016
→ UAPA में 2019 में बदलाव
→ विजयमदन लाल चौधरी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA कानून को कठोर बनाने की सराहना की।

वैश्वीकरण ने धनशोधन को ज्यादा गहरा कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संरक्षणवाद अपनाया जाये बल्कि साझे सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कानून को, सहमति को अपनाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. ऐसे तर्क दिए गए हैं कि भारत को बाह्य अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में अपनी कुछ पुरानी धारणाओं की समीक्षा करने और नए वैश्विक मानदंडों के विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

There have been arguments that India needs to review some of its past assumptions about the nature of outer space and contribute to the development of new global norms. In this context, analyse India's stand in relation to the Artemis Accords. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आउटर स्पेस ट्रीटी 1968 के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष का आशय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सीमाओं से परे साझे मानवता के आकाश है जिसकी सीमा कारमान लाइन (100km) से तय होती है।

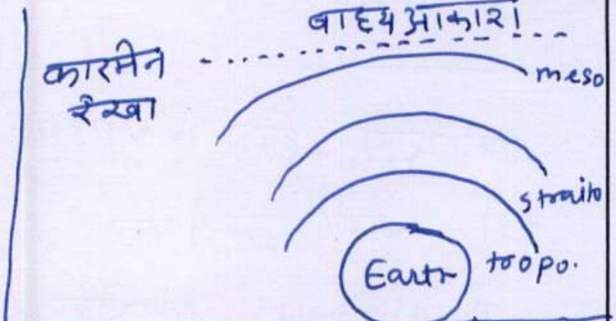

आर्टेमिस समझौता

- अमेरिका द्वारा प्रस्तावित चंद्रमा अन्वेषण अभियान हेतु वैश्विक सहमति निर्मित करने का घोषणा पत्र है, जिसे UK, कनाडा तथा कई देशों ने सहमति व्यक्त कर दी है
- आर्टेमिस समझौते अंतरिक्ष के मानवोपयोगी हितों के लिए साझा रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का दस्तावेज

भारत की धारणा

↳ UN COCUPUS समिति तथा आउटर स्पेस ट्रीटी में अंतरिक्ष को किसी देश की संपत्ति नहीं माना गया

- अंतरिक्ष मानवता का साझा है
- अंतरिक्ष को किसी देश के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जाये।
- अंतरिक्ष यात्री किसी एक देश के नहीं कहे जायेंगे, वे मानवता के होंगे।

भारत और आर्टेमिस

पक्ष	विपक्ष
अंतरिक्ष क्षेत्र में NASA का नया अन्वेषण	- अंतरिक्ष संप्रभुता पर US प्रभुत्व
- India-US अंतरिक्ष सहयोग, NISAR आदि पर	- भारत के अपने चंद्र मिशन
- दक्षिणी ध्रुव (चंद्रमा) का अन्वेषण	- अमेरिकी एजेंसियां चीन के प्रतिद्वंद्व में
- संपूर्ण विश्व के हित में	- वैश्विक एकमत नहीं

नया दृष्टिकोण

- मिशन में सभी देशों के यात्री हैं प्रमुख
- तकनीक साझा
- अंतरिक्ष के लिए ग्लोबल गवर्नेंस की आवश्यकता

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हमें अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, वैज्ञानिक विकास के लिए रणनीतिक स्वायत्तता बनाते हुए अपनी धारणा को दृढ़ करने या परिवर्तन करने का अवसर उपलब्ध है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK